जनांदोलन बनाम हुकूमत

सामयिक

प्रभात कुमार रॉय

क्या भारत के करोड़ों जन गण अनाचारी, भ्रष्टाचारी और जालिम हुकूमत की हिंसक शक्ति से खौफजदा होकर खामोश बैठ जाएंगे। अपने साम्राज्य में सूर्यास्त न देखने वाली ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने वाले भारतवासियों की संतानें कदाचित इतनी निर्बल नहीं कि काले अंग्रेजों की राजसत्ता को शिकस्त न दे सकें।

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सन 1977 के आम चुनाव के ऐतिहासिक सबक को कांग्रेस ने पूर्णतः विस्मृत कर दिया है। यदि कांग्रेस ऐतिहासिक सबक को विस्मृत न करती तो यकीनन उसकी कयादत में काम करने वाली हुकूमत 5 जून 2011 की काली रात में अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर इतने बर्बर और वहशियाना तरीके से प्रहार न करती। पूर्णतः अहिंसक विरोध प्रदर्शन का ऐसा ही हश्र किया जाएगा, तो भारतवासियों को नक्सलपंथियों की हिंसक भाषा समझ आने का खतरा भयानक तौर पर बढ़ सकता है। क्या राजसत्ता का जन्म वस्तुतः संवैधानिक कानून कायदे और नैतिकता से सराबोर रूल ऑफ लॉ से होता है अथवा कामरेड माओ के अल्फाज में सिर्फ बंदूक की नली से होता है। यह मुद्दा सदैव जेर ए बहस रहा है। संजीदा सवाल है कि नक्सलपंथियों के साथ ही क्या मनमोहन सिंह हुकूमत भी बाकायदा मानने लगी है कि राजसत्ता का जन्म बंदूक की नली से ही होता है। यदि ऐसा है तो 25 जून 1975 के बाद एक बार फिर 5 जून 2011 की घटना के बाद भारत का गणतंत्र खतरे में है। सभी राष्ट्रभक्त ताकतों और गणतंत्र में गहन यकीन करने वाले नागरिकों और राजनीतिक दलों को यथाशीघ्र एकजुट होना चाहिए। शर्मनाक स्थिति तब और विकट हो जाती है, जबकि कांग्रेस नेतृत्व अपने कुकृत्य पर शर्मिंदा होने और पश्चाताप करने के स्थान पर बेशर्मी से उसकी पैरोकारी करते नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने शानदार ढंग से मामले का संज्ञान लेकर मनमोहन सिंह सरकार को कटघरे खड़ा कर दिया है।

भारत के जन जीवन में उदारता, सहिष्णुता, विचारों का खुलापन, बहस मुबाहिसा और शास्त्रार्थ युगों-युगों से रचे बसे हैं। गणतांत्रिक परम्पराएं भारत में उस दौर से कायम हैं, जब अजातशत्रु के सामंती सम्राट के रूप में उदित होने से पूर्व भारतीय धरा पर अनेक गणतंत्र सदियों से अस्तित्व में रहे थे। महात्मा बुद्ध का जन्म भी ऐसे ही गणतंत्र में हुआ था, जिसे लिच्छवी गणतंत्र के तौर पर जाना जाता था। इंग्लैंड और अमेरिका का विश्व सभ्यता के नक्शे पर उदय भी नहीं हुआ था, उस दौर में भारतवर्ष ने ऐतिहातिक रूप से यूनान, मिश्र, और रोमन सभ्यता संस्कृति के साथ खड़े होकर कदम बढ़ाए थे। वैचारिक संकीर्णता और धर्मांधता का प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कहीं कोई स्थान रहा ही नहीं। वादे वादे जायते तत्व बोधा के महामंत्र का उदघोष करके ऋषियों मुनियों ने वैचारिक मतभेदों का सदैव स्वागत किया और वैचारिक लंदात्मकता को तत्व ज्ञान हासिल करने का मूलमंत्र करार दिया। भारतीय चिंतन परंपरा में वैचारिक मतभेदों को शत्रुता के तौर पर कदाचित निरूपित नहीं किया गया।

गणतंत्र में अहिंसक विरोध प्रदर्शन तो वस्तुतः राजसत्ता के कार्यकलापों और नीतियों के विरुद्ध सकारात्मक वैचारिक असहमति का परिचायक रहे हैं। भारतीय गणतंत्र के संविधान निर्माताओं ने जोकि जंग ए आजादी के अत्यंत उत्कृष्ट योद्धा भी रहे, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में वैचारिक आजादी और अहिंसक विरोध प्रदर्शन को बाकायदा महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। आजादी के आंदोलन के दौर में गणतांत्रिक विचारों और संस्कारों में दीक्षित राष्ट्रीय कांग्रेस ने सत्तानशीन होकर बहुत जल्द इन संस्कारों को विस्मृत कर दिया, जबकि 1957 में केरल में कम्युनिस्टों की कयादत में सत्ता में आई विपक्ष की प्रथम प्रांतीय सरकार को बिना किसी ठोस कारण के बर्खास्त कर दिया गया। यह घोर अलोकतांत्रिक बर्खास्तगी पं नेहरू काल में कांग्रेस हुकूमत में पनपी और पल्लवित हुई तानाशाही प्रवृति के कारण। 1975 में आपातकाल राष्ट्र पर आयद कर दिया गया, केवल इस कारण कि इंदिरा गांधी सरकार की नीतियों की मुखालफत में लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष अहिंसक विरोध प्रदर्शनों में एकजुटता की ओर बढ़ रहा था। आपातकाल में लाखों लोग सिर्फ इसलिए जेलों में ठूंस दिए गए और लाखों को पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार होने के लिए विवश कर दिया गया कि वे राजसत्ता के नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। 1977 के आम चुनाव में भारतीय जनमानस ने कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त देकर, उसे ऐतिहासिक सबक सिखाया।

दिल्ली के रामलीला मैदान को भारत का थ्यानमैन चौक बना देने वाले राजसत्ता के मद में चूर घोर अहंकारी राजनेताओं को भारत का जनमानस बख्शेगा बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार के नए रिकार्ड कायम करने वाली मनमोहन सिंह सरकार भ्रष्टाचार के बरखिलाफ खड़े होने वाले जनआंदोलन की प्रत्येक मुहिम को कुचल डालने का रुख इख्तियार कर चुकी है। मनमोहन सिंह सरकार के रवैये के कारण उच्चतम स्तर पर शासकीय भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए अन्ना हजारे की जनलोकपाल बिल की मुहिम का हश्र भी देश के समक्ष है। अकूत काले धन का राष्ट्रीयकरण करने की बाबा रामदेव की मुहिम का अंजाम भी देश ने अश्रुपूरित आंखों से टीवी के परदे पर देख ही लिया। क्या भारत के करोड़ों जन गण अनाचारी, भ्रष्टाचारी और जालिम हुकूमत की हिंसक शक्ति से खौफजदा होकर खामोश बैठ जाएंगे। अपने साम्राज्य में सूर्यास्त न देखने वाली ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने वाले भारतवासियों की संतानें कदाचित इतनी निर्बल नहीं कि काले अंग्रेजों की राजसत्ता को शिकस्त न दे सकें। जातिवाद, धर्मांधता और क्षेत्रीय संकीर्णताओं को दरकिनार कर पूर्णरूपेण जागृत होकर भारतीय नागरिक आम चुनाव के दिन ही सभी भ्रष्ट अपराधी और अहंकारी राजनेताओं को इतिहास के कूड़ेदान में दफन कर सकते हैं। भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक व्यवस्था में देश के आम नागरिकों का यकीन कायम रहे, इसलिए बेहद जरूरी है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध और प्रदर्शन के मौलिक संवैधानिक अधिकारों की हिफाजत का काम राष्ट्र की न्यायपालिका अत्यंत दृढ़तापूर्वक अंजाम दे, अन्यथा कार्यपालिका के तौर पर काम करने वाली हुकूमत जब आम नागरिकों की अहिंसक आवाज को भी जब राजसत्ता की शक्ति के बलबूते पर कुचलने की कोशिश करती है तो वह अहिंसक प्रतिरोध को हिंसक आंदोलन में परिवर्तित होने की परिस्थिति का सृजन किया करती है। किसी भी गणतंत्र में अहिंसक प्रतिरोध और प्रदर्शन उसे ताकतवर बनाते हैं, क्योंकि ये सरकार के शांतिपूर्ण परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कामयाब गणतंत्र की यही पहचान रही है कि इसके तहत सत्ता और समाज जनगण की इच्छा शक्ति से बिना किसी खून खराबे के बदल सकते हैं।

(लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं)

Reproduced by www.hobbyshobby.com with author's permission